भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3766

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

उचित दर की दुकानें

3766. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
डॉ. आलोक कुमार सुमन:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री जय प्रकाश:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री शंकर लालवानी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों की आय बढ़ाने और उत्पादों के पोर्टफोलियों में सुधार करने के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन स्थानों सहित उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां जन पोषण केन्द्रों के आधुनिकीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा भविष्य में आधुनिकीकरण किए जाने के लिए प्रस्तावित जन पोषण केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) आधुनिकीकरण कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): भारत सरकार, राज्यों और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से उचित दर दुकानों (एफपीएस) को पोषण युक्त वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर-पीडीएस वस्तुओं के लिए इनवॉइस क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए सिडबी ने एक अनुकूलित ऐप- एफपीएस सहाय विकसित किया है जो कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करता है। सिडबी ने बी2बी ऑनलाइन थोक विक्रेता एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग किया है ताकि ये एफपीएस डीलर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इन एफपीएस (जिन्हें जन पोषण केंद्र-जेपीके भी कहा जाता है) के पास ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करने और एफपीएस सहाय का उपयोग करने के विकल्प हैं। वैकल्पिक रूप से, एफपीएस/जेपीके स्थानीय थोक विक्रेताओं/वितरण एजेंसियों के माध्यम से गैर-पीडीएस वस्तुएं भी प्राप्त कर रहे हैं।

...2/-

वर्तमान में, गुजरात (अहमदाबाद), तेलंगाना (हैदराबाद), राजस्थान (जयपुर) और उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद) राज्यों/जिलों में जन पोषण केंद्र (जेपीके) का प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया गया है। इस पायलट अध्ययन के तहत, 60 एफपीएस डीलरों (पहचान किए गए राज्यों/जिलों से प्रत्येक में 15 एफपीएस डीलर) को जन पोषण केंद्र में बदल दिया गया है।

राज्यों को, अपने राज्यों में जेपीके मॉडल को अपनी इच्छानुसार किसी भी संख्या तक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

*****